वर्ग—ख	I सहायक निदेशक	25
	II सहायक निदेशक (टंकण व आशुलिपि)	19
वर्ग—ग	I हिन्दी प्राध्यापक	245
	II अनुसधान सहायक	3
	III उच्च श्रेणी लिपिक	25
	IV आशुलिपिक ग्रेड-III	8
	V अवर श्रेणी लिपिक	53
वर्ग—घ	I दफ्तरी	2
	II चपरासी	95
	III चौकीदार	6

(ख) बयालीस ।

(ग) जी, नही ।

(घ) सहायक निदेशक के पदो पर शत प्रतिशत पदोन्नति हिन्दी प्राध्यापको से ही की जाती है और सरकार के विचार मे प्राध्यापको की पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

विभागाध्यक्ष जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं

6630. **श्री गोविन्द राम मोरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि केन्द्रीय सरकार मे कार्यरत अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियो मे सम्बन्धित विभागाध्यक्षो की सख्या कितनी है और कार्यलयो की कुल सख्या की तुलना मे उनका अनुपात क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) अपेक्षित सूचना सभी मंत्रालयो/विभागो से एकत्रित की जा रही है और इसे जितना जल्दी सम्भव होगा सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Public Sector intervention on Industries

6631. SHRI NARENDRA SINGH Will the Miniser of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the proposal for public sector intervention on Industries where existing producers in private sector resort to unfair practices is under consideration of Government,

(b) if so, such industries in private sector where Government propose to intervene, and

(c) details of the malpractices that such private sector industries are resorting to?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c). The role assigned to public sector has been clarified in para 21 of the Statement on Industrial Policy laid before the Lok Sabha by the Minister of Industry on 23rd December, 1977. Accordingly, there will be an expanding role for the public sector in several fields Not only will it be the producer of important and stratgic goods of basic nature, but it will also be used effectively as a stabilising force for maintaining essential supplies for the conusmer.

Guidelines to Paper Manufacturers

6632 SHRI AMAR ROY PRADHAN· Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have issued guidelines to paper manufacturers to restore the prices of paper prevailing before 31st December last; and

(b) if so, what are the guidelines in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI). (a) and (b) Although there is no statutory control on the prices of paper, Government have been discouraging the industry from resorting to unilateral increase in prices without adequate justification Government's unhappiness at the price increase effected by some mills, without consulting Government was conveyed to the paper industry at a meeting held in January, 1978 Government has stressed that the 1977 price level should be restored At the same time steps have been taken to increase the production of common varieties of writing and printing papers which is expected to ease the price situation The question of further regulatory measures as well as the possibility of imports, would be considered after studying the reaction of the Industry

T.V. Station at Panaji

6633 SHRI AMRUT KASAR Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state

(a) whether the proposal for setting up a T V station at Panaji, Goa, is under consideration,

(b) if the scheme is lagging due to paucity of funds whether the Government is aware that in their present visit to Goa the Yugoslavia team has suggested a scheme by which the programmes at the Bombay T V can be relayed to Goa within an expenditure of Rs 1,00,000/-, and

(c) Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L K ADVANI) (a) A proposal for setting up a Relay Transmitter at Panaji has been included in the draft Rolling Plan (1978-83) Its implementation however, will depend on availability of financial resources and priorities accorded by the Planning Commission.

(b) Government is not aware of any such suggestion

(c) Does not arise

विद्युत उत्पादन के उपकरणों का निर्माण

6634. श्री अमर सिंह ठाकुर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में घटिया किस्म के विद्युत उत्पादन के उपकरणों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आभा मयती) देश में निर्मित विद्युत अनिवार्य उपकरणों की किस्म नियंत्रण सुनिश्चित करने का ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनो क्षेत्रों के निर्माता ग्राहकों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं और किस्म नियंत्रण और सुधार जहां आवश्यक हो का सुनिश्चय करने की जिम्मेदारियों के प्रति आमतौर पर सचेत रहते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने बायलरों के सबसे बड़े उत्पादक और टर्बाइनों और जनरेटरों के एकमात्र उत्पादक के रूप में एक प्रसिद्ध विदेशी निर्माता के सहयोग से अधिक नये और उन्नत किस्म के बायलरों का उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। इनसे 200 से 1000 मे० वा० तक के तापीय टर्बो सेटों के लिए एक दूसरी प्रसिद्ध कम्पनी के साथ भी सहयोग किया है और इन सेटों का कार्य बढ़िया होगा और इनमें क्वालिटी पैरामीटर होंगे। कार्यशाला स्तर पर, विक्रेता वस्तुओं, पैकिंग, अधिष्ठापन और चालू करने के लिए अपेक्षित अन्य सभी आवश्यक अभ्युपाय किये जा रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक भी विदेशी तकनीकी सहायता, जहां आवश्यक हो, प्राप्त कर सकते हैं।